



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 154]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 1974/चैत्र 7, 1896

No. 154]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 1974/CHAITRA 7, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 1974

S.O. 217(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

ORDER

WHEREAS I, V. V. Giri, President of India, have received a report from the Administrator of the Union territory of Pondicherry and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the administration of the Union territory of Pondicherry cannot be carried on in accordance with the provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963) (hereinafter referred to as "the Act");

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 51 of the Act and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby—

(a) suspend, for a period of six months, in relation to the said Union territory of Pondicherry, the operation of the following provisions of the Act, namely:—

sub-section (1), and clause (a) of sub-section (2), of section 6;

in section 7, sub-sections (1), (3) and (4), clauses (b) and (c) of sub-section (2) and the first proviso to that sub-section, and so much of sub-section (5) as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker;

sections 8 to 12 (both inclusive), sections 15 to 17 (both inclusive), section 22 and section 24;

so much of sub-section (1) of section 30 as requires the previous approval of the President and so much of clause (c) of sub-section (3) of the same section as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker;

so much of sub-section (1) of section 30 as requires the previous approval of the President;

section 33, sub-section (2) of section 34 and section 36;

sections 44 and 45;

sub-section (1), and the following provision, namely, "whether taken on the advice of his Ministers or otherwise" in sub-section (2), of section 48; and

so much of section 50 as relates to the Council of Ministers; and

(b) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary and expedient for administering the Union territory of Pondicherry in accordance with the provisions of article 239 of the Constitution during the aforesaid period, namely:—

(i) the Legislative Assembly of the said Union territory is hereby dissolved;

(ii) in relation to the said Union territory, unless the context otherwise requires, any reference in sections 6, 23, 27, 28, 30 and 49 of the Act to the Administrator shall be construed as a reference to the President and any reference in sections 23, 27 to 31 (both inclusive), 48 and 49 to the Legislative Assembly of a Union territory by whatever form of words shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed as a reference to Parliament;

(iii) in relation to the said Union territory, the reference to the Legislative Assembly of Union territory in section 28 shall be construed as including a reference to Parliament.

V. V. GIRI,

President.

Dated the 28th March, 1974.

[No. F. U-11012/2/74-UTL]

K. R. PRABHU, Addl. Secy.

गृह मन्त्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1974

क्र० घा० 217 (अ) :—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनाएँ प्रकाशित किया जा रहा है :

आदेश

यतः मुझे, व वे० गिरी, भारत के राष्ट्रपति को, पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन मे एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उस रिपोर्ट तथा मुझे प्राप्त अन्य जानकारी पर विचार करने के पश्चात् मेरा यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन, संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता ;

अतः अब, इस अधिनियम की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उन निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं,—

(क) इस अधिनियम के निम्नलिखित उपबन्धों का प्रारम्भ, उक्त पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, छद्म भाग की अवधि के लिए निम्नलिखित करता हूँ, अर्थात् :—

धारा 6 की, उपधारा (1), और उपधारा (2) का खण्ड (क) ;

धारा 7 में, उपधारा (1), (3) और (4), उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) और उस उपधारा का प्रथम परन्तुक, और उपधारा (5) का उतना भाग जो उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों से संबंधित है ;

धारा 8 से 12 (जिनमें दोनों धारा सम्मिलित हैं), धारा 15 से 17 (जिनमें दोनों धारा सम्मिलित हैं), धारा 22 और धारा 24 ;

धारा 27 की उपधारा (1) का उतना भाग, जिसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है और उसी धारा की उपधारा (3) के खण्ड (ग) का उतना भाग जो उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों से संबंधित है ;

धारा 30 की उपधारा (1) का उतना भाग जिसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है ;

धारा 33, धारा 34 की उपधारा (2) और धारा 38 ;

धारा 44 और 45 ;

धारा 46 की, उपधारा (1) और उपधारा (2) में, निम्नलिखित उपबन्ध, अर्थात् “क्या अपने मंत्रियों की सलाह पर या अन्यथा लिया गया” ; और

धारा 50 का उतना भाग जो “मंत्रिपरिषद् से संबंधित है ; और

(ख) निम्नलिखित आनुवंशिक और पारिणामिक उपबन्ध बनाता हूँ जो मुझे पूर्वोक्त अधिध के दौरान संविधान के अनुच्छेद 239 के उपबन्धों के अनुसार पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन करने के लिए आवश्यक और मशीवीन प्रतीत होते हैं, अर्थात् :—

(i) उक्त संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा भंग की जाती है ;

(ii) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उक्त संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, इस अधिनियम की धारा 6, 23, 27, 28, 30 और 49 में प्रस्तावक के प्रति किसी निर्देश का अर्थ राष्ट्रपति के प्रति निर्देश लगाया जाएगा, और धारा 23, 27 से 31 (जिनमें दोनों धारा सम्मिलित हैं), 48 और 49 में किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के प्रति किन्हीं भी शब्दों में निर्देश का, जहां तक उसका संबंध उसके कृत्यों और उनकी शक्तियों से है, अर्थ, संसद के प्रति निर्देश लगाया जाएगा ;

- (iii) उक्त संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, धारा 26 में किसी संघ राज्यक्षेत्र को विधान सभा के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि उसके अस्तगंत संसद के प्रति निर्देश भी है।

तारीख : 28 मार्च, 1974

य० बे० गिरि,

राष्ट्रपति ।

[नं० एफ० यू०-11012/2/74-यू टी एल]

के० धार० प्रभु, सपर सचिव ।